भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब

बजट का मुख्य लक्ष्य दुनिया में प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को मजबूत बनाना

नई दिल्ली, 02 फरवरी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने कहा है कि बजट 2026-27 भारत को इनोवेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है. इस बजट का मुख्य लक्ष्य दुनिया में प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को मजबूत बनाना है.

एसबीआई चेयरमैन के अनुसार, इस बजट में नीतियों की निरंतरता बनी हुई है और टैक्स सिस्टम को लेकर भी स्पष्टता है. बजट में ग्रामीण और शहरी इलाकों, पुराने सेक्टर और नए उभरते सेक्टरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है. उन्होंने एसबीआई की 'यूनियन बजट 2026-27 एनालिसिस रिपोर्ट' में कहा कि इस साल का बजट एक तरफ अनुमानित तो दूसरी तरफ भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बजट का ढांचा पहले जैसा ही है, जिसमें रोजगार पैदा करने वाले और उभरते सेक्टरों पर ध्यान दिया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अब भी बजट का मजबूत आधार बना हुआ है और इसमें निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव है. सेट्टी ने कहा कि इस बजट में बैंकिंग सेक्टर के लिए कई अच्छे मौके हैं. बदलते समय के साथ बैंकिंग सिस्टम को नया रूप देना और वित्तीय बाजारों को स्थिर रखना जरूरी है ताकि भारत की अगली विकास यात्रा को सही दिशा मिल सके.

> तेजी से बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए बजट में शहरों के समूहों की ताकत का उपयोग करने की योजना बनाई गई है. इसके तहत सिटी इकनॉमिक रीजन (सीईआर) तय किए जाएंगे और हर सीईआर को 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. सेट्टी ने कहा कि उभरते हुए क्षेत्रों में बजट में मौजूदा भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लाया जाएगा ताकि उपकरण, सामग्री और भारतीय तकनीक विकसित की जा सके. साथ ही, क्रिटिकल मिनरल्स की कमी को देखते हुए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने और पूंजीगत सामान के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव है.

ग्रीन एनर्जी से दवाओं तक, ड्यूटी में बड़ी छूट

नई दिल्ली, 2 फरवरी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2026 में कस्टम ड्यूटी दरों में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है, जिसका सीधा असर उद्योग और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. सरकार ने रणनीतिक रूप से उन कच्चे माल और जरूरी कंपोनेंट्स पर ड्यूटी घटाई है, जिनका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन, डिफेंस और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में होता है. रेयर-अर्थ मिनरल मोनाजाइट पर ड्यूटी 2.5त्न से घटाकर शून्य कर दी गई है. सोलर ग्लास में उपयोग होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर 7.5त्न से घटाकर जीरो ड्यूटी लागू होगी. बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने वाले कैपिटल गुड्स पर भी अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी.

बजट : एनआरआई की आसान हुई राहें

पुरानी समस्याओं को भी काफी हद तक दूर किया गया है

एनआरआई के लिए निवेश का माहौल साफ, सरल और भरोसेमंद

नई दिल्ली, 02 फरवरी. एक अमेरिकी नीति विशेषज्ञ के अनुसार, भारत के केंद्रीय बजट से साफ संकेत है कि नई दिल्ली ग्लोबल कैपिटल, टैलेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को आकर्षित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है. इस पूरी रणनीति के केंद्र में प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई को रखा गया है. यह बजट भारत के आत्मविश्वास को दिखाता है.

फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज में नीति और पॉलिसी और स्ट्रेटेजी चीफ खंडेराव कांड ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है, जब दुनिया भर में आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है. इसके बावजूद बजट भारत के आत्मविश्वास को दिखाता है.

उन्होंने बताया कि बजट में एनआरआई के लिए भारतीय इक्विटी में निवेश करना पहले से ज्यादा आसान बना दिया गया है. व्यक्तिगत और कुल निवेश की सीमा बढ़ाने से एनआरआई अब सीधे बाजार में अधिक आसानी और भरोसे के साथ निवेश कर सकेंगे.

इसके साथ ही, एनआरआई से जुड़े संपत्ति लेन-देन की पुरानी समस्याओं को भी काफी हद तक दूर किया गया है. नए बदलावों से कंप्लायंस का बोझ कम होगा और विदेश में रहने वाले भारतीय अपनी संपत्ति को आसानी से बेच या खरीद सकेंगे, जिससे रियल एस्टेट बाजार में तरलता बढ़ेगी. खंडेराव कांड ने कहा कि ये सभी कदम मिलकर एनआरआई के लिए निवेश का माहौल साफ, सरल और ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं.

शेयर बाजारों में लौटी तेजी

प्रमुख सूचकांक एक प्रतिशत से ज्यादा चढ़े

मुंबई, 02 फरवरी. बजट के दिन रही भारी गिरावट के बाद सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी लौट आयी और प्रमुख सूचकांक एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए.

बीएसई का सेंसेक्स 943.52 अंक (1.17 प्रतिशत) चढ़कर 81,666.46 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 262.95 अंक यानी 1.06 फीसदी की तेजी के साथ 25,088.40 अंक पर बंद हुआ. बजट के दिन रविवार को विशेष सत्र में दोनों सूचकांक करीब दो प्रतिशत लुढ़क गये थे. शेयर बाजारों की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई, लेकिन बाद में अच्छी लिवाली देखी गयी. रुपये में तेजी से बाजार में निवेश धारणा को समर्थन मिला. रुपया फिलहाल 41.50 पैसे की वृद्धि के साथ 91.52 रुपये प्रति डॉलर पर है. मझौली और छोटी कंपनियों में भी तेजी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.22 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.64 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. वाहनों की बिक्री के मजबूत आंकड़े आने से सेक्टर में तेजी रही. तेल एवं गैस, धातु, एफएमसीजी, रियलटी, रसायन, बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के समूहों में भी लिवाली हावी रही.

तीन दिन में चांदी 1.60 लाख टूटी, सोना भी लुढ़का!

1.40 लाख पर आया सोना

2.41 लाख के पास पहुंची चांदी

सोने पर मार्जिन 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत पहुंचा

चांदी पर 11 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया गया है

नई दिल्ली, 02 फरवरी. बजट के एक दिन बाद ही गोल्ड और सिल्वर मार्केट में तेज गिरावट का सिलसिला जारी है. लगातार तीसरे कारोबारी दिन चांदी और सोने की कीमतों में बड़ी टूट देखने को मिली.

रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, वहीं अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर मार्जिन बढ़ने से ट्रेडर्स पर अतिरिक्त दबाव बना. वायदा बाजार और सर्राफा बाजार दोनों में गिरावट का असर दिख रहा है, जिससे बुलियन बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है. सोना और चांदी, जो कुछ दिन पहले तक ऐतिहासिक ऊंचाई पर कारोबार कर रहे थे, अब तेज गिरावट के दौर में हैं. 29 जनवरी को चांदी 4.01 लाख प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई थी, जो अब गिरकर 2.41 लाख पर ट्रेड कर रही है. यानी तीन दिनों में करीब 1.60 लाख की गिरावट दर्ज की गई. इसी तरह सोना 1.69 लाख प्रति 10 ग्राम से फिसलकर 1.40 लाख पर आ गया है. सर्राफा बाजार में भी चांदी 29,255 और सोना 6,427 सस्ता हुआ है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, चांदी 2,36,496 प्रति किलो और 24 कैरेट सोना 1,42,270 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.

पिछले कुछ दिनों से सोना - चांदी में ऐतिहासिक तेजी के बाद चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है. अब तक चांदी में 9 फीसदी की गिरावट आई है. एमसीएक्स पर एक ही दिन में करीब 27प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई, जिससे भाव 3 लाख प्रति किलो से नीचे आ गए.

निवेशकों ने बड़े पैमाने पर बिकवाली की

विशेषज्ञों के अनुसार गिरावट की पहली बड़ी वजह प्रॉफिट बुकिंग है. रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर बिकवाली की. दूसरी बड़ी वजह शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज द्वारा सोना और चांदी पर मार्जिन मनी बढ़ाना है. सोने पर मार्जिन 6प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत और चांदी पर 11प्रतिशत से 15प्रतिशत कर दिया गया है. इससे ट्रेडर्स पर अतिरिक्त फंड जमा करने का दबाव बना, जिसके चलते मजबूरन पोजिशन काटनी पड़ी. मार्जिन बढ़ने का सीधा असर यह होता है कि जिन ट्रेडर्स ने पहले से खरीदारी कर रखी होती है, उनसे एक्स्ट्रा रकम मांगी जाती है.

संतुलित और विकसित भारत के लक्ष्य वाला बजट : उद्योग जगत

नई दिल्ली, 02 फरवरी. उद्योग जगत ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को विकासोन्मुख, संतुलित और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है.

उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजीव जुनेजा ने रविवार को जारी बयान में कहा कि बजट आर्थिक वृद्धि को तेज और स्थायी बनाने, लोगों की आकांक्षाओं को सशक्त साझेदारी में बदलने और विकास के अवसरों तक समावेशी पहुंच बनाने के तीन कर्तव्यों को पूरा करती है. उन्होंने बताया कि 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय बुनियादी ढांचे को मजबूती देगा और आपूर्ति चेन की बाधाओं को दूर करेगा. पीएचडीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं महासचिव डॉ. रंजीत मेहता ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा को सेमीकंडक्टर निर्माण से जोड़ते हुए लिथियम-आयन सेल्स और सोलर ग्लास निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट तथा परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए छूट को 2035 तक बढ़ाना अहम कदम है.

रक्षा क्षेत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएचडीसीसीआई रक्षा एवं एचएलएस समिति के चेयर अशोक अतलुरी ने कहा कि 7.85 लाख करोड़ रुपये का रक्षा आवंटन और 75 प्रतिशत घरेलू खरीद अनिवार्यता रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में निर्णायक संकेत है.

> एमएसएमई सेक्टर पर बजट के प्रभाव को रेखांकित करते हुए एएमए हर्बल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के को-फाउंडर एवं सीईओ यावर अली शाह ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड और 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स को पुनर्जीवित करने का निर्णय छोटे उद्योगों के लिए बड़ा सहारा बनेगा. फुटकर (रिटेल) और खपत (कंजम्पशन) आधारित अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए भूटानी इंफ्रा के सीईओ आशीष भूटानी ने कहा यह बजट भारत की रिटेल अर्थव्यवस्था में उपभोग आधारित विकास चक्र की मज़बूत नींव रखता है.

मारुति ने जनवरी में 2.37 लाख वाहन बेचे

नई दिल्ली, 02 फरवरी. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने जनवरी में मासिक बिक्री का रिकॉर्ड बनाते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 2,36,963 वाहन बेचे जो जनवरी 2025 के मुकाबले 11.64 प्रतिशत अधिक है.

कंपनी ने सोमवार को बताया कि घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की उसकी बिक्री 1,74,529 इकाई रही जो 0.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. यात्री वाहनों में कारें, उपयोगी वाहन और वैन आते हैं. इसके अलावा, हल्के वाणिज्यिक वाहन सुपर कैरी की बिक्री एक साल पहले के 4,089 से घटकर 3,771 इकाई रह गयी. दूसरी कंपनी के वाहनों की बिक्री 7,643 इकाई रही. इस प्रकार घरेलू बाजार में उसकी कुल बिक्री 1,85,943 इकाई रही जो 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि है. निर्यात के मामले में कंपनी का प्रदर्शन

शानदार रहा. उसने जनवरी में 51,020 वाहनों का निर्यात किया जबकि पिछले साल जनवरी में यह आंकड़ा 27,100 इकाई पर रहा था. टाटा मोटर्स पैसेंजनर व्हीकल्स के यात्री वाहनों की कुल बिक्री जनवरी 47.1 प्रतिशत बढ़कर 71,066 इकाई पर पहुंच गयी. इसमें घरेलू बाजार में उसने 70,222 वाहन बेचे जो 46.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

एयर इंडिया ने शंघाई के लिए शुरू की उड़ान

नई दिल्ली, 02 फरवरी. टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने छह साल बाद रविवार को चीन के शंघाई के लिए उड़ान शुरू की. कंपनी ने बताया कि दिल्ली-शंघाई उड़ान एआई352 ने दोपहर बाद 12.07 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान किया. एयरलाइन इस मार्ग पर बोइंग 787-8 विमान का इस्तेमाल कर रही है. यह सेवा सप्ताह में चार दिन उपलब्ध होगी. कंपनी ने उसके लिए विशेष रूप से तैयार बोइंग 787-9 विमान का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है.

जनवरी में फिर बढ़ी विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार

मुंबई, 02 फरवरी. उत्पादन और नये ऑर्डरों में मजबूत वृद्धि के दम पर देश के विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार माह-दर-माह आधार पर जनवरी में एक बार फिर बढ़ गयी.

एचएसबीसी द्वारा जारी भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का खरीद प्रबंधक सूचकांक जो दिसंबर 2025 में 22 महीने के निचले स्तर 55.0 पर रहा था, जनवरी में 55.4 दर्ज किया गया. सूचकांक का 50 से ऊपर रहना क्षेत्र की गतिविधियों में बढ़ोतरी को दिखाता है जबकि इसका 50 से नीचे रहने गिरावट बताता है. वहीं, 50 का स्तर स्थिरता दर्शाता है. भारत में एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश की विनिर्माण कंपनियों ने जनवरी में गतिविधियों में दोबारा सुधार देखा. इसके पीछे मुख्य कारक थे - नये ऑर्डरों, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि. लागत हल्की बढ़ी है जबकि विक्रय मूल्य में कमी आयी है. इससे उत्पादकों का लाभ अनुपात थोड़ा प्रभावित हुआ है.

समाचार विशेष

नीतीश की आधी आबादी पर भरोसे की लकीर

पटना. समृद्धि यात्रा के दौरान पहला चरण हो या कि दूसरा चरण, हर उस जगह पर दिए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सम्बोधन में कुछ कॉमन विषय था तो वह आधी आबादी की चिंता थी.

समृद्धि यात्रा के दौरान पश्चिम चम्पारण से लेकर दूसरे चरण की अंतिम समृद्धि यात्रा पर आधी आबादी के विकास की चिंता ही हावी थी. और दूसरे चरण की समृद्धि यात्रा समाप्त कर जब पटना पहुंचे तो कैबिनेट की बैठक में आधी आबादी यानी महिला वोटर्स के हित को साधते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा भी कर दी.

आधी आबादी के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक एक बड़ी घोषणा के साथ खत्म हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर अंतिम मुहर लग गई. इस घोषणा के साथ ही यह राशि उन सफल महिलाओं को दो चरणों में दी जाएगी जो पूर्व में दिए गए 10 हजार की राशि का बेहतर इस्तेमाल कर लाभकारी व्यवसाय को अंजाम दिया. मगर जो महिला काफी बेहतर की और उसे दो लाख की राशि एक बार चाहिए तो उस पर विचार कर उचित पाया गया तो दे दी जाएगी.

सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट- मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका एक मात्र मकसद राज्य की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाना है. यही वजह भी है कि वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव के पहले राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 हजार की जो आर्थिक सहायता दी थी, अब उन महिलाओं को एक उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार ने दो लाख रुपये देने का रास्ता भी साफ कर विपक्ष की बोलती बंद कर दी.

नीतीश कुमार ने विपक्ष को दिया करारा जवाब

वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव का बंपर परिणाम जब एनडीए के पक्ष में आया तो राजद और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि 10 हजार देकर चुनाव जीत लिया, अब दो लाख किसे देते हैं देखना है? चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने भी तब कहा था कि अगर नीतीश कुमार की सरकार राज्य की 1.5 करोड़ महिलाओं से जो वादा किया है, 2-2 लाख रुपये दे दे, तो वे राजनीति छोड़ देंगे. कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने ममुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाज के लिए दो लाख देने की घोषणा कर विपक्ष दलों की बोलती बंद कर दी. अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेंगे?

लालू यादव की राजनीति का अंत!

क्या कठपुतली नेता बचा पाएंगे पार्टी, रोहिणी ने खड़े किए सवाल

पटना. तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के लिए लिखा है- सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप. पटाक्षेप यानी अंत.

तो क्या अब राजद में लालू यादव का दबदबा नहीं रहेगा? क्या लालू यादव पर जबरन रिटायरमेंट थोप दी गयी है? क्या अब लालू यादव सिर्फ दिखावे के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे? लालू यादव संयोग से जनता दल के अध्यक्ष बने थे, लेकिन राजद बनाया था देश के प्रधानमंत्री और अपने दल के वरिष्ठ नेताओं को चुनौती देकर. राजद केवल एक दल नहीं बल्कि लालू यादव की राजनीतिक शक्ति का एक प्रतीक है. चारा घोटाला में नाम आया, जेल गये, सजायाफ्ता हुए, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गये लेकिन एक दल के रूप राजद बिहार की ताकत बना रहा. ऐसे नेता को पार्टी का मुखौटा बना कर सीमित कर देना, एक युग का दुखद अंत है.

क्या अब लालू यादव शक्तिहीन हो गये ?- अगर लालू यादव शक्तिहीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो वास्तविक शक्ति कहां रहेगी? तेजस्वी यादव के पास? लेकिन रोहिणी आचार्य ने इस पर भी शंका जाहिर की है क्योंकि उन्होंने तेजस्वी को कठपुतली कार्यकारी अध्यक्ष बताया है. अगर रोहिणी आचार्य की माने तो अब पार्टी की वास्तविक शक्ति गिरोह-ए-घुसपैठ के पास रहेगी.

संयोग से बने थे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष

1990 के बाद मुख्यमंत्री लालू यादव बिहार के एक मजबूत नेता बन चुके थे. राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रभाव की चर्चा होने लगी थी. लेकिन जनवरी 1996 तक वे राष्ट्रीय राजनीति के बिग प्लेयर नहीं बने थे. लेकिन अचानक ही उनकी किस्मत बदल गयी. जनवरी 1996 में सीबीआइ ने हवाला कांड मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें कुल 25 नेताओं के नाम शामिल थे और वे जांच के दायरे में थे. उस समय जनता दल के अध्यक्ष कर्नाटक के एसआर बोम्मई थे.

बंगाल की राजनीति में नया मोड़

ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे हुमायूं

कोलकाता. टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने बड़ा फैसला किया है. अब उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाने का ऐलान किया है. वे एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे.

अल्पसंख्यक वोटों के लिहाज से यह गठबंधन काफी अहम माना जा रहा है. इसके साथ ही एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है. विधानसभा चुनाव से पहले हुगली में दल बदल की लहर चल रही है. युवा नेता देबब्रता बिस्वास जो कभी जिले के सप्तग्राम, मगरा और बंशबेरिया क्षेत्रों में प्रभावशाली नेता थे, अब राज्य की सत्ताधारी पार्टी में लौट आए हैं. टीएमसी में लौटने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें ईमानदारी से स्वीकार नहीं किया. इसीलिए अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए हैं.

देबब्रता उर्फ देबू 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके पार्टी बदलने से टीएमसी नेतृत्व हैरान है. वो 2013 से 2018 तक चुंचुरा मगरा पंचायत समिति के अध्यक्ष रहे हैं. टीएमसी ने उन्हें 2018 के पंचायत चुनावों में टिकट नहीं दिया था. तब टीएमसी नेतृत्व के साथ उनका मतभेद बढ़ा. उनकी लोकप्रियता जिले की राजनीति में उनके जनसमर्थन और समर्थकों की संख्या के कारण अच्छी थी. 2021 में, उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर सप्तग्राम विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन टीएमसी के दिग्गज नेता तपन दासगुप्ता से लगभग दस हजार वोटों से हार गए थे.

बीजेपी ने दी थी ये जिम्मेदारी

बीजेपी में रहते हुए उन्हें हुगली लोकसभा का सह-संयोजक बनाया गया था. सूत्रों के अनुसार, देबू काफी समय से पुरानी पार्टी की ओर झुकाव दिखा रहे थे. उन्हें बीजेपी के कार्यक्रमों में कम ही देखा गया था. हाल ही में मगरा में शुभेंदु अधिकारी के एक कार्यक्रम में बीजेपी के जिला नेतृत्व से उनकी दूरी स्पष्ट हो गई. विधानसभा में विपक्ष के नेता के जुलूस में अपने समर्थकों के साथ घुसने की कोशिश करने पर उन्हें रोक दिया गया. इसके बाद देबू बीजेपी के कार्यक्रमों में नज़र नहीं आए. यह बात जगजाहिर है कि देबू टीएमसी के संपर्क में थे.

विशेष अजित पवार के नहीं रहने से मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को झटका लगा है.

संभावना देख रही है कांग्रेस

मुंबई. महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी संभावना देख रही है. उनको लग रहा है कि अजित पवार के निधन के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है. संसद के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस के नेता इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अजित पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी का विलय शरद पवार की पार्टी के साथ हो जाएगा और शरद पवार पार्टी को एनडीए से बाहर करेंगे.

हालांकि कम से कम अजित पवार की पार्टी सरकार से बाहर नहीं होने जा रही है. पहले की तरह ही समीकरण बना रहेगा. अजित पवार की पार्टी के आठ नेता अभी सरकार में मंत्री हैं, जिनमें से सात कैबिनेट मंत्री हैं. वे न तो अभी सरकार से बाहर हो रहे हैं और न पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेवे जा रही है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तुरंत यह काम नहीं होगा. लेकिन अब महाराष्ट्र में नया समीकरण बनेगा. उनके ऐसा मानने का आधार यह है कि अजित पवार के नहीं रहने से मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को झटका लगा है. अब एकनाथ शिंदे सरकार के ऊपर दबाव बढाएंगे. कांग्रेस के एक जानकार नेता का कहना है कि अजित पवार एक्स फैक्टर थे, जिनसे भाजपा को ताकत मिली हुई थी और वह एकनाथ शिंदे के दबाव का जवाब दे पाती थी. अब फिर से भाजपा को अलग थलग करने की राजनीति शुरू हो सकती है. मुंबई के मेयर के चुनाव में ही इसकी परीक्षा हो जाएगी. अगर दोनों एनसीपी का विलय हुआ तो उनके विधायकों की संख्या 51 और लोकसभा सांसदों की संख्या आठ होगी. इससे भाजपा भी दबाव में आएगी. कांग्रेस के नेता यहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा को छोड़ कर सभी पार्टियां एक मंच पर आ सकती हैं. गौरतलब है कि भाजपा के 132 विधायक हैं, जो बहुमत से 13 कम है. हालांकि यह बहुत दूर की कौड़ी है लेकिन अगर पूरी एनसीपी की कमान शरद पवार के हाथ में आती है तो राजनीति निश्चित रूप से दिलचस्प होगी.